



*The*  
**ACHIEVERS**  
IAS ACADEMY  
PATNA

*Daily*  
**NEWS CHRONICLE**

**IDEAL FOR**

For UPSC/BPSC & For other Exams

**Hindi**

**NEWS CREDIT**

PIB/ PTI/ News On Air/ The Hindu/ IANS/ Business Standard/ Times Of India/ Deccan Herald/ Hindustan Times/ BBC News/ Aljazeera/ Mirror.Uk/ Times Now/ Economic Times/ Financial Express/ Indian Express...

**NEWS COVERED**

Business News, financial news, economy news, company news, politics news, India news, breaking news, Indian economy, International News, Sports News, and many more topics...



**Wednesday, July 15, 2026**



+91 8434931877



[www.achieversiaspatna.co.in](http://www.achieversiaspatna.co.in)



[achieversiaspatna@gmail.com](mailto:achieversiaspatna@gmail.com)

## दिन की प्रमुख घटनाएं

- भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए चार स्वदेशी नौसेना प्लेटफार्मों को शामिल किया
- यूक्रेन और नौ यूरोपीय देशों ने एकीकृत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा वास्तुकला के लिए गठबंधन शुरू किया
- भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आठ महीने के पहले मिशन की शुरुआत की
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत निर्मित वेगा प्रोसेसर का उपयोग करके स्वदेशी ड्रोन विकास को बढ़ावा देने के लिए एनआईडीएआर 2.0 लॉन्च किया
- दिल्ली सरकार ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया
- अमेरिका, ब्रिटेन और बारह देशों ने चीन के समुद्री दावों के खिलाफ 2016 के दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले की पुष्टि की
- अहमदाबाद ने मियावाकी विधि का उपयोग करके एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
- न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक माओरी हाका का स्वागत किया गया
- आदित्य बिड़ला समूह 1.8 अरब डॉलर के नवीकरणीय ऊर्जा सौदे में शेल की स्प्रिंग एनर्जी का अधिग्रहण करेगा
- सीसीआई ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस निविदाओं में बोली में हेराफेरी के लिए एचपी इंडिया पर 126.87 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया



## एक महीने के भीतर चार स्वदेशी नौसेना प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल हुए



- भारतीय नौसेना ने एक महीने की अवधि के भीतर चार नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्मों को शामिल किया है, जो आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की समुद्री रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करता है।
- नवीनतम जोड़ आईएनएस महेंद्रगिरि है, जो छठा प्रोजेक्ट 17 ए (नीलगिरि-श्रेणी) स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसे विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया है।
- इससे पहले, नौसेना ने आईएनएस दुनागिरि (प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ फ्रिगेट), आईएनएस संशोधक (सर्वे वेसल लार्ज), और आईएनएस एग्रा (एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट) को शामिल किया था।
- ये शामिल भारत के स्वदेशी युद्धपोत-निर्माण कार्यक्रम में एक प्रमुख मील का पत्थर हैं और कई समुद्री भूमिकाओं में नौसेना की परिचालन तत्परता को बढ़ाते हैं।

### नौसेना में शामिल किए गए नए प्लेटफॉर्म:

- आईएनएस महेंद्रगिरि – प्रोजेक्ट 17ए (नीलगिरि श्रेणी) स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट।
- आईएनएस दुनागिरि - प्रोजेक्ट 17 ए स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट।
- आईएनएस संशोधक - सर्वेक्षण पोत (बड़ा)।
- आईएनएस आगरे - पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट (एसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी)।

### प्रोजेक्ट 17A के बारे में:

- प्रोजेक्ट 17ए प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक-क्लास) स्टील्थ फ्रिगेट का अनुवर्ती कार्यक्रम है।
- इसमें सात उन्नत स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण शामिल है।

### जहाजों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है:

- मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल), मुंबई
- गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), कोलकाता

### फ्रिगेट से सुसज्जित हैं:

- उन्नत चुपके सुविधाएँ
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल
- बराक-8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली
- आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली
- स्वदेशी युद्ध प्रबंधन प्रणाली।

### INS महेंद्रगिरि के बारे में:

- वर्ग: नीलगिरि-वर्ग (परियोजना 17 ए)।
- प्रकार: स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट।
- कमीशन: 11 जुलाई 2026।
- नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम।
- द्वारा कमीशन किया गया: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
- यह छठा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट है और इसमें उन्नत स्वचालन, उत्तरजीविता और स्टील्थ तकनीक शामिल है।

### INS संशोधक के बारे में:

### एक सर्वेक्षण पोत (बड़ा) जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है:

- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण
- तटीय और गहरे समुद्र का मानचित्रण
- समुद्र विज्ञान डेटा संग्रह
- सुरक्षित नेविगेशन और समुद्री बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन।

### INS Agary के बारे में:

- एक पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले पानी का जहाज (ASW-SWC)।

### के लिए डिज़ाइन किया गया:

- तटीय जल में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें बेअसर करना।
- कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन का संचालन करें।
- बंदरगाहों और अपतटीय संपत्तियों की रक्षा करें।

### भारतीय नौसेना के बारे में:

- स्थापना: 26 जनवरी 1950 (आधुनिक भारतीय नौसेना)।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- आदर्श वाक्य: शन नो वरुण: ("महासागरों का स्वामी हमारे लिए शुभ हो")।

- नौसेना प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन

- भारतीय नौसेना भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- प्रोजेक्ट 17ए भारत के प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत-निर्माण कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य स्टील्थ, उत्तरजीविता और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है।
- नीलगिरि श्रेणी के युद्धपोत भारत में निर्मित सबसे उन्नत युद्धपोतों में से हैं और स्वदेशी और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस हैं।
- जीआरएसई (गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स) और एमडीएल (मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड) दो प्रमुख रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (डीपीएसयू) हैं जो स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में लगे हुए हैं।
- भारत ब्लू वाटर नेवी बनने के दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जो हिंद महासागर के गहरे जल और उससे आगे के समुद्र में काम करने में सक्षम है।
- हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा शिपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- संगठन: भारतीय नौसेना।
- उपलब्धि: एक महीने के भीतर चार स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफार्मों को शामिल किया गया।
- नवीनतम प्रेरण: आईएनएस महेंद्रगिरि।
- वर्ग: प्रोजेक्ट 17ए (नीलगिरि-क्लास) स्टील्थ फ्रिगेट।
- अन्य प्लेटफार्म: आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस एग्रे।
- कार्यक्रम: परियोजना 17 ए।
- शिपबिल्डर्स: मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई)।
- उद्देश्य: स्वदेशी नौसैनिक क्षमता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना।
- इनिशिएटिव: आत्मनिर्भर भारत
- भारतीय नौसेना मुख्यालय: नई दिल्ली।
- नौसेना प्रमुख: एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन

### यूक्रेन और नौ यूरोपीय देशों ने यूरोप की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए गठबंधन बनाया



- यूक्रेन और नौ यूरोपीय देशों ने बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बढ़ते खतरे के खिलाफ महाद्वीप की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यूरोप की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए गठबंधन के गठन की घोषणा की है।
- यह घोषणा पेरिस, फ्रांस में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की गई, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं ने भाग लिया।
- गठबंधन का उद्देश्य तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और मिसाइल हमलों का मुकाबला करने में यूक्रेन के युद्ध के मैदान के अनुभव को जोड़कर एक एकीकृत यूरोपीय एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा वास्तुकला विकसित करना है।

#### भाग लेने वाले देश:

- यूक्रेन

- डेनमार्क
- फ्रांस
- जर्मनी
- इटली
- नीदरलैंड
- नॉर्वे
- स्पेन
- स्वीडन
- यूनाइटेड किंगडम।

#### बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) के बारे में:

- एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) प्रणाली को उनकी उड़ान के विभिन्न चरणों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने, ट्रैक करने, अवरोधन करने और नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

#### एक विशिष्ट बीएमडी प्रणाली में शामिल हैं:

- प्रारंभिक चेतावनी रडार
- उपग्रह और निगरानी प्रणाली



- कमांड और कंट्रोल नेटवर्क
- इंटरसेप्टर मिसाइलें

- बैलिस्टिक मिसाइलें बहुत तेज गति से यात्रा करती हैं और एक बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का पालन करती हैं, जिससे उन्हें क्रूज मिसाइलों की तुलना में रोकना अधिक कठिन हो जाता है। सफल बीएमडी के लिए स्तरित और एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता होती है।

#### नाटो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के बारे में:

- नाटो यूरो-अटलांटिक क्षेत्र के बाहर उत्पन्न होने वाले बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से सदस्य देशों की रक्षा के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) प्रणाली संचालित करता है।

#### यह एकीकृत करता है:

- ग्राउंड-आधारित इंटरसेप्टर
- रडार सिस्टम
- नौसेना की संपत्ति
- कमांड और नियंत्रण बुनियादी ढांचा

- नए गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा राष्ट्रीय या नाटो प्रणालियों को बदलने के बजाय यूरोप की रक्षा क्षमताओं को पूरक करना है।

#### यूक्रेन के बारे में:

- राजधानी: कीव।
- मुद्रा: यूक्रेनी रिव्निया (UAH)।
- राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की।
- यूक्रेन 2022 से रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के खिलाफ खुद का बचाव कर रहा है, हवाई और मिसाइल रक्षा में व्यापक परिचालन अनुभव प्राप्त कर रहा है।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

**भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए आठ महीने के पहले मिशन की शुरुआत की**

- भारतीय मूल के नासा के अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने कजाकिस्तान के बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रोस्कोस्मोस सोयुज एसएस -29 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए अपना पहला अंतरिक्ष मिशन शुरू कर दिया है।

- बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रारंभिक प्रक्षेपण चरण के दौरान संचालित किया जाता है और फिर गुरुत्वाकर्षण के तहत एक बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का पालन किया जाता है।
- क्रूज मिसाइलें जहाज पर प्रणोदन का उपयोग करके कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और आम तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में अधिक चलने योग्य होती हैं।
- यूरोप यूरोपीय स्काई शील्ड इनिशिएटिव (ईएसएसआई) का भी अनुसरण कर रहा है, जो एक अलग बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसका उद्देश्य कई यूरोपीय देशों को शामिल करते हुए एक एकीकृत जमीन-आधारित वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना है।
- आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों में देश की रक्षा वास्तुकला के आधार पर पैट्रियट, एसएएमपी/टी, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, थाड और एरो सिस्टम जैसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा (IAMDR) निगरानी, अवरोधन, कमान और नियंत्रण, और विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा की कई परतों को जोड़ती है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- शामिल देश: यूक्रेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम।
- पहल: यूरोप की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए गठबंधन।
- घोषणा स्थल: पेरिस, फ्रांस।
- उद्देश्य: यूरोप के लिए एक साझा एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता विकसित करना।
- फोकस: एकीकृत यूरोपीय मिसाइल रक्षा वास्तुकला।
- खतरे को संबोधित किया गया: बैलिस्टिक मिसाइलें।
- यूक्रेनी राष्ट्रपति: वलोडिमिर ज़ेलेंस्की।
- संबंधित यूरोपीय पहल: यूरोपीय स्काई शील्ड पहल (ईएसएसआई)।
- यूक्रेन की राजधानी: कीव।
- यूक्रेन मुद्रा: यूक्रेनी रिव्निया (UAH)।

- इस मिशन के लगभग आठ महीने तक चलने की उम्मीद है, जिसके दौरान मेनन अभियान 74 और 75 के हिस्से के रूप में फ्लाइट इंजीनियर के रूप में काम करेंगे।
- उनके साथ रोस्कोस्मोस के कॉस्मोनॉट प्योत्र डबरोव और अन्ना किकिना भी हैं। मिशन के दौरान, चालक दल चंद्रमा और मंगल ग्रह पर भविष्य के मानव

मिशनों का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और चिकित्सा प्रयोग करेगा।



**अनिल मेनन के बारे में:**

- राष्ट्रीयता: अमेरिकी (भारतीय मूल का)।
- व्यवसाय: नासा अंतरिक्ष यात्री, आपातकालीन चिकित्सा चिकित्सक, मैकेनिकल इंजीनियर।
- नासा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित: 2021।
- पूर्व भूमिका: स्पेसएक्स की पहली उड़ान सर्जन।
- सैन्य सेवा: कर्नल, अमेरिकी अंतरिक्ष बल।
- उन्होंने नासा के मानव अनुसंधान कार्यक्रम के साथ भी काम किया और वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के चिकित्सा सहायता में योगदान दिया। मेनन के पिता भारतीय मूल के हैं, जबकि उनकी मां यूक्रेनी मूल की हैं।

#### अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) दुनिया का सबसे बड़ा रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह है और स्थायी रूप से चालक दल वाली अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में कार्य करता है।
- यह लगभग 400 किमी की औसत ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है और लगभग हर 90 मिनट में एक परिक्रमा पूरी करता है।

**आईएसएस एक सहयोगी परियोजना है जिसमें शामिल हैं:**

- नासा (संयुक्त राज्य अमेरिका)
- रोस्कोस्मोस (रूस)
- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए)
- जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA)
- कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (सीएसए)
- स्टेशन जीव विज्ञान, चिकित्सा, भौतिकी, पृथ्वी अवलोकन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान का समर्थन करता है।

#### नासा के बारे में:

- फुल फॉर्म: नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
- स्थापित: 1958.
- मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका।
- नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, वैमानिकी अनुसंधान और वैज्ञानिक मिशनों के लिए जिम्मेदार है।

#### रोस्कोस्मोस के बारे में:

- आधिकारिक नाम: अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रोस्कोस्मोस राज्य निगम।
- देश: रूस।
- मुख्यालय: मास्को, रूस।
- रोस्कोस्मोस रूस के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए जिम्मेदार है।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- सोयुज रूस का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और दुनिया के सबसे विश्वसनीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों में से एक है।
- कजाकिस्तान में स्थित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, दुनिया की पहली और सबसे बड़ी परिचालन अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा है। यहीं से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान यूरी गगारिन ने 1961 में प्रक्षेपण किया था।
- आईएसएस नवंबर 2000 से लगातार बसा हुआ है, जिससे यह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक लगातार कब्जे वाली मानव चौकी बन गई है।
- लंबी अवधि के आईएसएस मिशन भविष्य के आर्टेमिस चंद्र मिशनों और मंगल ग्रह के अंतिम मानव अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हैं।
- भारत इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे अपने पहले स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन, गगनयान की भी तैयारी कर रहा है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- व्यक्ति जो चर्चा में है: अनिल मेनन।
- संगठन: नासा।
- मिशन: सोयुज एमएस-29।
- गंतव्य: अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस)।
- मिशन की अवधि: लगभग 8 महीने।
- आईएसएस अभियान: 74 और 75।
- लॉन्च साइट: बैकोनूर कॉस्मोड्रोम, कजाकिस्तान।
- सह-चालक दल के सदस्य: प्योत्र डबरोव और अन्ना किकिना (रोस्कोस्मोस)।
- नासा की स्थापना: 1958।
- नासा मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी., यूएसए।



- आईएसएस भागीदार एजेंसियां: नासा, रोस्कोस्मोस, ईएसए, जेएएक्सए, सीएसए।
- संबंधित भारतीय मिशन: गगनयान।

**इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत निर्मित चिप्स द्वारा संचालित ड्रोन विकसित करने के लिए NIDAR**

## 2.0 लॉन्च किया



- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) के सहयोग से स्वयंसेवक पहल के तहत ड्रोन एप्लिकेशन एंड रिसर्च (NIDAR 2.0) के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों, शोधकर्ताओं और नवप्रवर्तकों को भारत के स्वदेशी वेगा प्रोसेसर द्वारा संचालित स्वायत्त ड्रोन विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।
- एनआईडीएआर 2.0 भाग लेने वाली टीमों के लिए स्टार्टअप इनक्यूबेशन, क्लाउड क्रेडिट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और इंडस्ट्री इंटरनशिप के साथ-साथ 65 लाख रुपये से अधिक का पुरस्कार पूल प्रदान करता है।

### प्रमुख विशेषताएं:

- प्रतिभागी वेगा प्रोसेसर, एक स्वदेशी आरआईएससी-वी-आधारित माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग करके स्वायत्त ड्रोन सिस्टम का निर्माण करेंगे।
- चुनौती में वास्तविक दुनिया की समस्या के विवरण शामिल हैं जैसे:**

- आपदाओं के दौरान खोज और बचाव।
- स्वायत्त झुंड ड्रोन संचालन।
- सटीक कृषि और स्मार्ट निगरानी।

### विजेता टीमों को प्राप्त होगा:

- स्टार्टअप ऊष्मायन समर्थन।
- क्लाउड कंप्यूटिंग क्रेडिट।
- सॉफ्टवेयर विकास उपकरण।
- कॉर्पोरेट इंटरनशिप।
- उद्योग विशेषज्ञों से मेंटरशिप।

### NIDAR 2.0 के बारे में:

- फुल फॉर्म: ड्रोन एप्लिकेशन एंड रिसर्च के लिए नेशनल इनोवेशन चैलेंज।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्वयंसेवक पहल के तहत आयोजित किया गया।
- भारत द्वारा डिजाइन किए गए प्रोसेसर का उपयोग करके स्वदेशी स्वायत्त ड्रोन प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अगली पीढ़ी के ड्रोन समाधान बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और स्टार्टअप के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है।

### स्वयंसेवक पहल के बारे में:

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान, कौशल और सेमीकंडक्टर-आधारित ड्रोन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एक मजबूत स्वदेशी ड्रोन इकोसिस्टम का निर्माण करना है।
- ड्रोन डिजाइन और विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

### वेगा प्रोसेसर के बारे में:

- डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी (डीआईआर-वी) कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है।
- सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) द्वारा डिजाइन किया गया।
- ओपन-सोर्स RISC-V इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (ISA) पर आधारित।
- यह स्वदेशी सेमीकंडक्टर और एम्बेडेड कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों के निर्माण के भारत के प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है।

### ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI) के बारे में:

- भारत का अग्रणी उद्योग निकाय ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
- ड्रोन निर्माण, नवाचार, नीति समर्थन और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।

- भारत के ड्रोन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार, उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के साथ सहयोग किया
- अध्यक्ष: विपुल सिंह
- अध्यक्ष: स्मित शाह

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- आरआईएससी-वी एक ओपन-स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर (आईएसए) है जो देशों को मालिकाना लाइसेंसिंग के बिना प्रोसेसर डिजाइन करने में सक्षम बनाता है।
- भारत ने नियमों को सरल बनाने और ड्रोन निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन नियम, 2021 लॉन्च किया।
- घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2021 में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की गई थी।
- स्टार्टअप के माध्यम से ड्रोन को एक सेवा (ड्रोन-एज-ए-सर्विस) के रूप में बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में ड्रोन शक्ति पहल की घोषणा की गई थी।
- सटीक कृषि, आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निरीक्षण, रक्षा, रसद, स्वास्थ्य देखभाल, खनन और सर्वेक्षण में ड्रोन का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

- कार्यक्रम: NIDAR 2.0 (ड्रोन एप्लिकेशन और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती)।
- मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई)।
- पार्टनर: ड्रोन फेडरेशन इंडिया (DFI)।
- पहल: स्वयान।
- लॉन्च की तारीख: 13 जुलाई 2026।
- पुरस्कार पूल: ₹65 लाख से अधिक।
- प्रयुक्त प्रौद्योगिकी: स्वदेशी वेगा प्रोसेसर।
- प्रोसेसर आर्किटेक्चर: आरआईएससी-वी।
- प्रोसेसर डेवलपर: सी-डैक।
- उद्देश्य: भारत निर्मित चिप्स द्वारा संचालित स्वायत्त ड्रोन विकसित करना।
- संबंधित पहल: डिजिटल इंडिया आरआईएससी-वी (डीआईआर-वी) कार्यक्रम।
- सहायक दृष्टि: आत्मनिर्भर भारत और सेमीकंडक्टर मिशन।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

**दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है।**



- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली सरकार ने आधिकारिक तौर पर अपनी प्रमुख महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया है।
- इस योजना का उद्देश्य वित्तीय सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान करना है। दिल्ली सरकार ने लाभार्थी सत्यापन और प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद रक्षाबंधन के आसपास इस योजना को शुरू करने की योजना बनाई है।

- 21-60 वर्ष की आयु की महिलाएं।
- निर्धारित अवधि के लिए दिल्ली का स्थायी निवासी।
- अधिसूचित सीमा के भीतर वार्षिक पारिवारिक आय।
- प्रति परिवार केवल एक पात्र महिला।
- आवेदक या परिवार के सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
- अन्य विस्तृत पात्रता शर्तों को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

#### दिल्ली लक्ष्मी योजना के बारे में:

- यह महिला समृद्धि योजना का नया नाम दिया गया संस्करण है।
- डीबीटी के माध्यम से पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करना और घरेलू वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है।
- कार्यान्वयन की निगरानी संबंधित विभागों के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी।

#### संभावित पात्रता मानदंड:

#### प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के बारे में:



- 2013 में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया।
- कल्याणकारी लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करता है।
- सब्सिडी वितरण में लीकेज, दोहराव और देरी को कम करता है।

#### JAM ट्रिनिटी से जुड़ा हुआ:

- जन धन खाते
- आधार
- मोबाइल

- डीबीटी डिजिटल इंडिया का एक प्रमुख घटक है और सरकारी लाभों की पारदर्शिता और कुशल वितरण को बढ़ावा देता है।

#### दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के बारे में:

- स्थिति: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी)।
- संवैधानिक प्रावधान: संविधान का अनुच्छेद 239AA (69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 द्वारा डाला गया)।
- दिल्ली में एक विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद् है, जबकि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के अधीन रहती है।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उद्देश्य लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे कल्याणकारी लाभों का लक्षित और पारदर्शी हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।

- JAM ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल) भारत की डिजिटल कल्याण वितरण प्रणाली की रीढ़ है।
- अनुच्छेद 239एए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- 69वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1991 ने दिल्ली के लिए विधान सभा और मुख्यमंत्री के कार्यालय का निर्माण किया।
- वित्तीय समावेशन में सुधार और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए राज्यों द्वारा महिला केंद्रित डीबीटी योजनाओं को तेजी से अपनाया जा रहा है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- योजना: दिल्ली लक्ष्मी योजना।
- फॉर्मर नेम : महिला समृद्धि योजना
- राज्य/केंद्र शासित प्रदेश: दिल्ली (एनसीटी)।
- लाभ: ₹2,500 प्रति माह।
- स्थानांतरण मोड: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
- लाभार्थी: आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पात्र महिलाएं।
- उद्देश्य: महिलाओं का वित्तीय सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा।
- लॉन्च लक्ष्य: रक्षा बंधन 2026 के आसपास।
- संबंधित पहल: JAM ट्रिनिटी।
- दिल्ली के लिए संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 239AA
- प्रासंगिक संविधान संशोधन: 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1991।

### अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य देशों ने चीन के समुद्री दावों के खिलाफ 2016 के दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले की

#### पृष्ठ की



- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और 12 अन्य देशों ने संयुक्त रूप से 2016 दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता पुरस्कार की पृष्ठ की है, जिसमें कहा गया है कि चीन के विस्तृत समुद्री दावों का अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है।

- संयुक्त बयान स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (पीसीए), द हेग द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले की 10 वीं वर्षगांठ पर जारी किया गया था, जो फिलीपींस द्वारा समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत लाए गए एक मामले में दिया गया था।
- भाग लेने वाले देशों ने अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने वाली बलपूर्वक कार्रवाइयों का विरोध किया। हालांकि, चीन ने दोहराया कि वह 2016 के फैसले को मान्यता नहीं देता है और न ही उसे स्वीकार करता है।

#### संयुक्त वक्तव्य का समर्थन करने वाले देश:

- संयुक्त राज्य अमेरिका

- यूनाइटेड किंगडम
- ऑस्ट्रेलिया
- कनाडा
- चेक गणराज्य
- फ़िनलैंड
- फ़्रांस
- जर्मनी
- जापान
- नीदरलैंड
- न्यूजीलैंड
- फिलीपींस
- डेनमार्क
- लिथुआनिया

- यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी एक अलग बयान जारी किया जिसमें 2016 मध्यस्थ पुरस्कार.

#### उद्देश्य:

- के अधिकार की पुष्टि करें 2016 दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता पुरस्कार.
- समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करें।
- UNCLOS के सिद्धांतों को बनाए रखें।
- अंतरराष्ट्रीय जल में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
- इंडो-पैसिफिक में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था को बढ़ावा देना।

#### महत्व:

- नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के लिए अंतराष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करता है।
- समुद्री विवादों को हल करने में अंतराष्ट्रीय मध्यस्थता के महत्व पर प्रकाश डाला
- यह दक्षिण चीन सागर में तनाव को लेकर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता को दर्शाता है।
- फिलीपींस और अन्य दावेदार राज्यों के लिए राजनयिक समर्थन को मजबूत करता है।

#### के बारे में 2016 दक्षिण चीन सागर पंचाट पुरस्कार:

- 12 जुलाई 2016 को यूएनसीएलओएस के अनुलग्नक VII के तहत गठित एक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया।
- फिलीपींस ने 2013 में चीन के खिलाफ मामला शुरू किया था।

#### न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया कि:

- चीन के "नाइन-डैश लाइन" दावे का यूएनसीएलओएस के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है।
- यूएनसीएलओएस द्वारा मान्यता प्राप्त समुद्री क्षेत्रों से परे संसाधनों पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है।
- स्प्रेटली द्वीप समूह में कई विवादित समुद्री विशेषताएं कानूनी रूप से "चट्टानें" या कम-ज्वार की ऊंचाई हैं और 200-समुद्री मील विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के हकदार नहीं हैं।
- चीन की बड़े पैमाने पर भूमि सुधार गतिविधियों ने प्रवाल भित्तियों को पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाया।
- न्यायाधिकरण ने द्वीपों पर संप्रभुता के सवाल पर फैसला नहीं किया या समुद्री सीमाओं का परिसीमन नहीं किया। चीन ने इस पुरस्कार को "अमान्य और शून्य" बताकर खारिज कर दिया।

#### दक्षिण चीन सागर के बारे में:

- पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अर्ध-संलग्न समुद्र।

#### द्वारा सीमाबद्ध:

- चीन
- ताइवान
- फिलीपींस
- वियतनाम
- मलेशिया
- ब्रुनेई
- इंडोनेशिया

- यह क्षेत्र मत्स्य पालन, हाइड्रोकार्बन में समृद्ध है, और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जिसमें सालाना लगभग एक-तिहाई वैश्विक समुद्री व्यापार होता है।

#### UNCLOS के बारे में:

- पूर्ण रूप: समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन।
- अपनाया गया: 1982।



- लागू हुआ: 1994।
- "महासागरों के संविधान" के रूप में जाना जाता है।

**परिभाषित करता है:**

- प्रादेशिक सागर (12 समुद्री मील)
- सन्निहित क्षेत्र (24 समुद्री मील)
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) (200 समुद्री मील)
- महाद्वीपीय शेल्फ
- तटीय और समुद्री राज्यों के अधिकार और जिम्मेदारियां।

**स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के बारे में:**

- स्थापित: 1899.
- मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड।
- राज्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के बीच मध्यस्थता और विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है।
- पीसीए ने UNCLOS के तहत दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता कार्यवाही का संचालन किया।

**अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:**

- "नाइन-डैश लाइन" चीन की सीमांकन रेखा है जो दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% हिस्से को कवर करती है, जो कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के ईईजेड के साथ ओवरलैप होती है।
- दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, स्कारबोरो शोल और प्रातास द्वीप समूह शामिल हैं, जो सभी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
- अत्यधिक समुद्री दावों को चुनौती देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों द्वारा नेविगेशन ऑपरेशंस (एफओएनओपी) की स्वतंत्रता का आयोजन किया जाता है।

**अहमदाबाद ने एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया**



- अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने मियावाकी वनीकरण पद्धति का उपयोग करके केवल एक घंटे में 3.61 लाख (361,000) पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।

- भारत यूएनसीएलओएस के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और निर्बाध वाणिज्य की स्वतंत्रता की वकालत करता है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) एक तटीय राज्य की आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है, जिसके भीतर तटीय राज्य के पास प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु अधिकार हैं।

**परीक्षा फोकस बिंदु:**

- मुद्दा: दक्षिण चीन सागर विवाद।
- संयुक्त वक्तव्य: अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य देश।
- कानूनी आधार: 2016 दक्षिण चीन सागर पंचाट पुरस्कार.
- मध्यस्थता निकाय: मध्यस्थता का स्थायी न्यायालय (पीसीए), हेग।
- कन्वेंशन: समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS)।
- द्वारा दायर मामला: फिलीपींस (2013)।
- पुरस्कार दिया गया: 12 जुलाई 2016।
- मुख्य निष्कर्ष: चीन की नाइन-डैश लाइन का UNCLOS के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है।
- चीन की स्थिति: फैसले को अस्वीकार करता है और मान्यता नहीं देता है।
- पीसीए मुख्यालय: हेग, नीदरलैंड।
- UNCLOS अपनाया गया: 1982।
- UNCLOS लागू हुआ: 1994।
- सामरिक जल निकाय: दक्षिण चीन सागर।

- गुजरात के अहमदाबाद के बाहरी इलाके में स्थित भदज में 12 जुलाई 2026 को छात्रों, नगरपालिका कर्मचारियों, गैर सरकारी संगठनों, एनसीसी कैडेटों और नागरिकों सहित 25,000 से अधिक स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ मेगा वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अभियान ने 2023 में असम वन विभाग द्वारा स्थापित 3,31,929 पौधों के पिछले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लगभग 76,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में लगभग 35 स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों को लगाया गया, जिससे अहमदाबाद के सबसे बड़े शहरी वनों में से एक बनने की उम्मीद है।

**मियावाकी विधि के बारे में:**

- एक जापानी वनस्पतिशास्त्री डॉ. अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित।

- एक घने वनीकरण तकनीक जो देशी पौधों की प्रजातियों का उपयोग करती है जो एक साथ लगाए जाते हैं।
- ऐसे जंगल बनाता है जो 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और पारंपरिक वृक्षारोपण की तुलना में लगभग 30 गुना घने हो जाते हैं।
- प्रारंभिक विकास चरण के बाद तुलनात्मक रूप से कम रखरखाव की आवश्यकता होती है।
- शहरी वनीकरण, जैव विविधता बहाली और कार्बन पृथक्करण के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

#### गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में:

- 1955 में स्थापित।
- मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।
- दुनिया भर में उत्कृष्ट मानवीय उपलब्धियों और प्राकृतिक अभिलेखों को पहचानता है और सत्यापित करता है।

#### अहमदाबाद नगर निगम (AMC) के बारे में:

- अहमदाबाद शहर के प्रशासन के लिए जिम्मेदार शहरी स्थानीय निकाय।
- नागरिक बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, शहरी नियोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण पहल के लिए जिम्मेदार।
- यह वृक्षारोपण अभियान अहमदाबाद और गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हरित आवरण बढ़ाने की एक व्यापक पहल का हिस्सा है।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- एक घंटे में सबसे अधिक पौधे लगाने का पिछला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड असम वन विभाग के पास था, जिसने 15 सितंबर 2023 को 3,31,929 पौधे लगाए थे।

- यह वृक्षारोपण अभियान गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए "हरियाली लोकसभा" पहल से जुड़ा हुआ है।
- स्वदेशी (देशी) प्रजातियां स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित होती हैं, कम रखरखाव की आवश्यकता होती है, और स्थानीय जैव विविधता का समर्थन करती हैं।
- शहरी वन शहरी ताप द्वीप प्रभाव को कम करने, भूजल पुनर्भरण में सुधार करने, धूल प्रदूषण को कम करने और पक्षियों और कीड़ों के लिए आवास प्रदान करने में मदद करते हैं।
- भारतीय शहरों में खराब शहरी भूमि को बहाल करने और पारिस्थितिक लचीलेपन में सुधार के लिए मियावाकी पद्धति को तेजी से अपनाया जा रहा है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- उपलब्धि: वृक्षारोपण के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड।
- शहर: अहमदाबाद, गुजरात।
- आयोजन एजेंसी: अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी)।
- दिनांक: 12 जुलाई 2026।
- पौधे लगाए गए: एक घंटे में 3.61 लाख।
- प्रतिभागी: 25,000 से अधिक स्वयंसेवक।
- प्रयुक्त विधि: मियावाकी विधि।
- मियावाकी विधि के डेवलपर: डॉ. अकीरा मियावाकी (जापान)।
- लगाए गए प्रजातियां: लगभग 35 स्वदेशी प्रजातियां।
- पिछला रिकॉर्ड धारक: असम वन विभाग (2023)।
- गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम।

### प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड में माओरी हाका का स्वागत माओरी संस्कृति और भारत की मार्शल आर्ट परंपराओं पर

#### प्रकाश



- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की यात्रा के दौरान पारंपरिक माओरी हाका औपचारिक स्वागत किया गया, जो 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है।

- हाका प्रदर्शन ने न्यूजीलैंड के स्वदेशी लोगों माओरी की सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डाला और सम्मान, एकता, शक्ति और आतिथ्य का प्रतीक है।
- इस यात्रा में भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।
- इस आयोजन ने भारत की स्वदेशी मार्शल आर्ट सहित पारंपरिक मार्शल और सांस्कृतिक प्रदर्शन परंपराओं में नए सिरे से रुचि पैदा की है।

#### माओरी हाका के बारे में:

- हाका न्यूजीलैंड के स्वदेशी पॉलिनेशियन लोगों माओरी का एक पारंपरिक औपचारिक प्रदर्शन है।



- मूल रूप से साहस और एकता प्रदर्शित करने के लिए लड़ाई से पहले किया जाता था, अब इसका उपयोग किया जाता है:
- विशिष्ट अतिथियों का स्वागत है।
- महत्वपूर्ण अवसरों का जश्न मनाएं।
- उपलब्धियों और पूर्वजों का सम्मान करें।
- सामूहिक पहचान, सम्मान, दुःख या उत्सव व्यक्त करें।

#### हाका गठबंधन करता है:

|                                        |
|----------------------------------------|
| ● लयबद्ध जप।                           |
| ● शरीर की जबरदस्त हरकतें।              |
| ● पैर मुद्रांकन।                       |
| ● हाथ के इशारे।                        |
| ● तीव्र चेहरे के भाव और आंखों की हरकत। |

#### महत्त्व:

- माओरी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देता है और संरक्षित करता है।
- साहस, एकता, पहचान और सामुदायिक भावना का प्रतिनिधित्व करता है।
- न्यूजीलैंड की स्वदेशी परंपराओं के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में कार्य करता है।
- न्यूजीलैंड की All Blacks रग्बी टीम के माध्यम से व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जो अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले हाका का प्रदर्शन करती है।

#### भारत की प्रमुख पारंपरिक मार्शल आर्ट:

##### कलारीपयट्टू (केरल):

- दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक।
- सशस्त्र और निहत्थे युद्ध, लचीलेपन, योग और आयुर्वेद को जोड़ती है।
- परंपरागत रूप से परशुराम को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

##### सिलंबम (तमिलनाडु):

- प्राचीन स्टाफ-आधारित मार्शल आर्ट।
- संगम साहित्य में इसका उल्लेख किया गया है।
- प्राथमिक हथियार के रूप में बांस के डंडे (सिलंबम) का उपयोग करता है।

##### थांग-ता (मणिपुर):

- पारंपरिक मणिपुरी मार्शल आर्ट।
- इसमें तलवार (थांग) और भाला (ता) तकनीक शामिल है।

- मणिपुरी संस्कृति और अनुष्ठानों से निकटता से जुड़ा हुआ है।

##### गतका (पंजाब):

- पारंपरिक सिख मार्शल आर्ट।
- सिख गुरुओं के काल के दौरान विकसित।
- तलवारबाजी, लाठी लड़ाई और आत्मरक्षा का प्रदर्शन करता है।

##### मर्दानी खेल (महाराष्ट्र):

- पारंपरिक मराठा मार्शल आर्ट।
- तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध के मैदान की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है।

##### पाइका अखाड़ा (ओडिशा):

- पाइका योद्धा समुदाय की पारंपरिक मार्शल आर्ट।
- एक्रोबेटिक आंदोलनों और नृत्य के साथ हथियार प्रशिक्षण को जोड़ती है।

##### मुस्ती युद्ध (उत्तर प्रदेश):

- प्राचीन भारतीय निहत्था युद्ध प्रणाली।
- घूंसे, लात, हाथापाई और शारीरिक कंडीशनिंग पर जोर देता है।

##### माओरी के बारे में:

- माओरी न्यूजीलैंड (एओटेरोआ) के स्वदेशी पॉलिनेशियन लोग हैं।
- वे 13 वीं और 14 वीं शताब्दी के बीच न्यूजीलैंड पहुंचे।
- उनकी संस्कृति मजबूत सामुदायिक मूल्यों, मौखिक परंपराओं, भाषा (ते रेओ माओरी), नक्काशी, बुनाई और हाका जैसे औपचारिक प्रदर्शनों पर आधारित है।

##### न्यूजीलैंड के बारे में:

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ● राजधानी: वेलिंगटन।                                                            |
| ● सबसे बड़ा शहर: ऑकलैंड।                                                        |
| ● मुद्रा: न्यूजीलैंड डॉलर (NZD)।                                                |
| ● प्रधान मंत्री: क्रिस्टोफर लक्सन।                                              |
| ● आधिकारिक भाषाएँ: अंग्रेजी, माओरी (ते रेओ माओरी), और न्यूजीलैंड सांकेतिक भाषा। |

##### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- वेटांगी की संधि (1840) को आधुनिक न्यूजीलैंड का संस्थापक दस्तावेज माना जाता है, जिस पर ब्रिटिश क्राउन और माओरी प्रमुखों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
- तेरेओ माओरी न्यूजीलैंड की तीन आधिकारिक भाषाओं में से एक है।
- न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम All Blacks ने एक सदी से भी अधिक समय से अंतरराष्ट्रीय मैचों से पहले हाका का प्रदर्शन किया है।
- पारंपरिक भारतीय मार्शल आर्ट युद्ध, आत्मरक्षा, शारीरिक फिटनेस और आध्यात्मिक अनुशासन के लिए विकसित हुए हैं, और कई में योग और आयुर्वेद के तत्व शामिल हैं।
- कलारीपयट्टू, सिलंबम और थांग-टा जैसे मार्शल आर्ट को भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय की योजना में शामिल किया गया है।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- पारंपरिक प्रदर्शन: माओरी हाका।

### आदित्य बिड़ला समूह 1.8 अरब डॉलर के सौदे में शेल की स्प्रिंग एनर्जी का अधिग्रहण करेगा



- आदित्य बिड़ला समूह ने अपनी अक्षय ऊर्जा शाखा आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड (ABRen) के माध्यम से शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट B.V. से 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹17,200 करोड़) के सौदे में Spring Energy के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसमें ऋण भी शामिल है।
- यह अधिग्रहण भारत के इतिहास में सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा लेनदेन में से एक है और समूह के स्वच्छ ऊर्जा पोर्टफोलियो को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगा।
- पूरा होने पर, ABRen की कुल अनुबंधित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर लगभग 9.3 GW हो जाएगी, जिससे यह भारत के सबसे बड़े एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्लेटफार्मों में से एक बन जाएगा।
- लेन-देन 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है, जो नियामक अनुमोदन के अधीन है।

#### स्प्रिंग एनर्जी के बारे में:

- भारत में एक अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा मंच।

- देश: न्यूजीलैंड।
- द्वारा प्रदर्शन किया गया: माओरी (न्यूजीलैंड के स्वदेशी लोग)।
- अवसर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह।
- 40 साल में न्यूजीलैंड की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री
- हाका का उद्देश्य: स्वागत, उत्सव, स्मरण और एकता और शक्ति की अभिव्यक्ति।
- संबंधित संधि: वैतांगी की संधि (1840)।
- प्रमुख भारतीय मार्शल आर्ट: कलारीपयट्टू, सिलंबम, थांग-ता, गतका, मर्दानी खेल, पाइका अखाड़ा, मुस्ती युद्ध।
- न्यूजीलैंड की राजधानी: वेलिंगटन।
- आधिकारिक स्वदेशी भाषा: तेरेओ माओरी।

- कई भारतीय राज्यों में सौर, पवन और हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं का विकास और संचालन करता है।
- वर्तमान पोर्टफोलियो में शामिल हैं:
- ~3.3 गीगावॉट परिचालन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता।
- ~1.7 गीगावॉट निर्माणाधीन अनुबंधित परियोजनाएं।
- लगभग 5 गीगावॉट का कुल अनुबंधित पोर्टफोलियो।
- शेल ने 2022 में एक्टिस से स्प्रिंग एनर्जी का अधिग्रहण किया।

#### आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स (ABRen) के बारे में:

- आदित्य बिड़ला समूह की प्रमुख कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अक्षय ऊर्जा शाखा।
- पर ध्यान केंद्रित करता है:**

- सौर ऊर्जा
- पवन ऊर्जा
- हाइब्रिड नवीकरणीय परियोजनाएं
- वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) हरित ऊर्जा समाधान

- अधिग्रहण कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार रणनीति को महत्वपूर्ण रूप से तेज करता है।

#### शेल पीएलसी के बारे में:



- एक बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी जिसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है।
- तेल, प्राकृतिक गैस, एलएनजी, पेट्रोकेमिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा में काम करता है।
- अपनी वैश्विक रणनीति के हिस्से के रूप में, शेल चयनित नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों को विभाजित करते हुए उच्च-रिटर्न वाले व्यवसायों को प्राथमिकता देकर अपने पोर्टफोलियो का पुनर्गठन कर रहा है।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के तहत 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में सौर, पवन, जल विद्युत, बायोमास और लघु पनबिजली शामिल हैं।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है।

**नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन करने वाली प्रमुख सरकारी पहलों में शामिल हैं:**

- राष्ट्रीय सौर मिशन
- पीएम-कुसुम योजना
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

- सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
- चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत अक्षय ऊर्जा का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- भारत में प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में अडानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी शामिल हैं।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- अधिग्रहणकर्ता: आदित्य बिड़ला रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एबीआरईएन)।
- मूल कंपनी: आदित्य बिड़ला समूह (ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड)।
- लक्ष्य कंपनी: स्पिंग एनर्जी।
- विक्रेता: शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बी.वी.
- डील वैल्यू: US\$1.8 बिलियन (₹17,200 करोड़)।
- व्यवसाय की प्रकृति: नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन, हाइड्रिड)।
- अधिग्रहण के बाद नवीकरणीय पोर्टफोलियो: लगभग 9.3 गीगावॉट।
- अपेक्षित समापन: 2026 का अंत (नियामक अनुमोदन के अधीन)।
- नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नोडल मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)।
- भारत की गैर-जीवाश्म क्षमता लक्ष्य: 2030 तक 500 गीगावॉट।

**CCI ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) निविदाओं में बोली-हेराफेरी के लिए HP इंडिया पर ₹126.87 करोड़ का जुर्माना लगाया**



- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से सरकारी खरीद में गुटबंदी और बोली-हेराफेरी में शामिल होने के लिए HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पर ₹126.87 करोड़ का जुर्माना लगाया है।
- आयोग ने पाया कि एचपी इंडिया ने 2017 और 2020 के बीच व्यक्तिगत सिस्टम उत्पादों के लिए जीईएम निविदाओं में हेरफेर करने के लिए अपने अधिकृत पुनर्विक्रेताओं के साथ समन्वय किया, जिससे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। एचपी इंडिया के अलावा, पांच अधिकृत पुनर्विक्रेताओं और उनके अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया गया

था। कंपनियों को इस तरह की प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया गया था।

#### CCI के निष्कर्ष:

- एचपी इंडिया ने अपने अधिकृत पुनर्विक्रेताओं को बोली की कीमतें निर्धारित कीं।
- कंपनी ने निर्माता प्राधिकरण प्रपत्रों (एमएएफ) को नियंत्रित करके पुनर्विक्रेता भागीदारी में हेरफेर किया।
- पुनर्विक्रेताओं ने स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय अपनी बोलियों का समन्वय किया।
- इस आचरण ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर दिया और सरकारी खरीद प्रक्रिया को विकृत कर दिया।

#### लागू किए गए कानूनी प्रावधान:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3(1) प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करती है जो प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं या होने की संभावना रखते हैं।
- धारा 3(3)(d) विशेष रूप से उद्यमों के बीच बोली-हेराफेरी या मिलीभगत वाली बोली लगाने पर रोक लगाती है।
- धारा 27 सीसीआई को प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं के खिलाफ जुर्माना लगाने और निर्देश जारी करने का अधिकार देती है।
- धारा 46 उन उद्यमों के लिए कम दंड (उदारता) योजना प्रदान करती है जो स्वेच्छा से कार्टेल गतिविधियों का खुलासा करते हैं और जांच में सहयोग करते हैं।
- धारा 48 कंपनियों द्वारा उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के दायित्व का प्रावधान करती है।

#### सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) के बारे में:

- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया।
- केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों और स्थानीय प्राधिकरणों के लिए वन-स्टॉप ऑनलाइन खरीद पोर्टल।

#### यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य:

- पारदर्शी खरीद।
- प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण।
- कागज रहित और कैशलेस लेनदेन।
- सार्वजनिक खरीद में अधिक दक्षता और जवाबदेही।
- जीईएम का प्रबंधन सरकारी ई-मार्केटप्लेस स्पेशल पर्सन व्हीकल (जीईएम एसपीवी) द्वारा किया जाता है।

#### भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के बारे में:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित।
- 2009 में चालू हो गया।
- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- चेयरपर्सन: रवनीत कौर
- इसके उद्देश्य हैं:
- प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकें।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना।
- उपभोक्ता हितों की रक्षा करें।
- भारतीय बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।

#### कार्टेलाइजेशन और बोली-हेराफेरी के बारे में:

- कार्टेलाइजेशन तब होता है जब प्रतिस्पर्धी फर्म गुप्त रूप से कीमतों को तय करने, बाजारों को विभाजित करने या प्रतिस्पर्धा को सीमित करने के लिए सहमत होती हैं।
- बोली-हेराफेरी कार्टेलाइजेशन का एक रूप है जहां बोलीदाता निविदा के परिणाम में हेरफेर करने के लिए मिलीभगत करते हैं, जिससे वास्तविक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है।
- दोनों प्रथाएं खरीद लागत बढ़ाती हैं और बाजार दक्षता को कम करती हैं।

#### अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 ने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969 को प्रतिस्थापित किया।
- प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र जैसे बदलाव पेश किए और लेनिंसी प्लस ढांचे के दायरे का विस्तार किया।
- कम दंड (उदारता) योजना कार्टेल सदस्यों को कम दंड के बदले स्वेच्छा से प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए प्रमुख डिजिटल इंडिया पहलों में से एक है।
- बोली-हेराफेरी और कार्टेलाइजेशन को प्रतिस्पर्धा कानून के सबसे गंभीर उल्लंघनों में से एक माना जाता है क्योंकि वे सीधे निष्पक्ष बाजार प्रतिस्पर्धा को कमजोर करते हैं और सार्वजनिक खरीद के लिए लागत बढ़ाते हैं।

#### परीक्षा फोकस बिंदु:

- नियामक: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)।
- कंपनी को दंडित किया गया: एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
- जुर्माना: ₹126.87 करोड़।
- प्लेटफार्म: सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम)।
- उल्लंघन: गुटबंदी और बोली-हेराफेरी।
- प्रासंगिक कानून: प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002।
- प्रासंगिक अनुभाग: 3(1), 3(3)(डी), 27, 46, और 48।
- जीईएम लॉन्च: 2016।
- जीईएम का प्रशासनिक मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।
- सीसीआई प्रशासनिक मंत्रालय: कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय।
- सीसीआई मुख्यालय: नई दिल्ली।
- प्रतिस्पर्धा अधिनियम अधिनियमित: 2002।



## लेट्स रिवाइज

- ❖ जुलाई 2026 में कमीशन किया गया कौन सा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट, भारत के प्रोजेक्ट 17A (नीलगिरि-क्लास) कार्यक्रम के तहत छठा युद्धपोत बन गया? **आईएनएस महेंद्रगिरी**
- ❖ किस यूरोपीय राजधानी ने बैठक की मेजबानी की जहां यूक्रेन और नौ यूरोपीय देशों ने एक साझा बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता विकसित करने के लिए गठबंधन की घोषणा की? **पेरिस, फ्रांस**
- ❖ किस भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2026 में सोयुज MS-29 अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना पहला आठ महीने का मिशन शुरू किया? **अनिल मेनन**
- ❖ MeitY की स्वयंसेवक पहल के तहत स्वायत्त ड्रोन विकसित करने के लिए NIDAR 2.0 चुनौती में किस स्वदेशी प्रोसेसर का उपयोग किया जा रहा है? **VEGA प्रोसेसर (RISC-V आर्किटेक्चर पर आधारित)**
- ❖ 2026 में दिल्ली सरकार की किस योजना का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर "दिल्ली लक्ष्मी योजना" कर दिया गया? **महिला समृद्धि योजना**
- ❖ किस अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने 2016 में फैसला सुनाया कि दक्षिण चीन सागर में चीन के "नाइन-डैश लाइन" के दावों का यूएनसीएलओएस के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है? **मध्यस्थता के स्थायी न्यायालय (पीसीए), हेग**
- ❖ अहमदाबाद नगर निगम द्वारा एक घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए किस वनीकरण तकनीक का उपयोग किया गया था? **मियावाकी विधि**
- ❖ 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान उनका स्वागत करने के लिए स्वदेशी माओरी लोगों का कौन सा पारंपरिक औपचारिक प्रदर्शन किया गया था? **माओरी हाका**
- ❖ 2026 में घोषित 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे में आदित्य बिड़ला समूह द्वारा किस नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी का अधिग्रहण किया जा रहा है? **स्प्रिंग एनर्जी**
- ❖ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के किस प्रावधान के तहत बोली-हेराफेरी या मिलीभगत बोली लगाना विशेष रूप से निषिद्ध है? **प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3(3)(डी)**



# *The* **ACHIEVERS** IAS ACADEMY PATNA

## *Daily* **NEWS CHRONICLE**

### IMPORTANCE OF CURRENT AFFAIRS IN UPSC EXAMINATIONS

Current Affairs hold a crucial place in the preparation for the UPSC Civil Services Examination. A comprehensive understanding of recent national and international developments helps aspirants strengthen their General Studies foundation and develop a well-rounded perspective on important issues. Topics such as government policies, schemes, economy, international relations, science and technology, environment, defence, social justice, governance, reports, indices, appointments, awards, and major global events are highly relevant for both the Prelims and Mains examinations. Regular study of current affairs not only enhances factual knowledge but also improves analytical ability, critical thinking, answer-writing skills, and decision-making aptitude. Since UPSC questions often connect contemporary developments with static subjects, consistent preparation of current affairs enables aspirants to understand issues in depth and present balanced, informed, and relevant answers. It also plays an important role in Essay writing, Ethics, and the Personality Test, giving candidates a strong edge throughout the examination process.

### CONTACT US



+91 8434931877



achievers\_ias\_patna



PATLIPUTRA GOLAMBAR



ACHIEVERS IAS ACADEMY (UPSC/BPSC)



achieversiaspatna@gmail.com



Achievers IAS Academy



www.achieversiaspatna.co.in



Achievers IAS Academy, PATNA